



सीटू मजदूर

सी. आइ. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

29 सितंबर की देशव्यापी हड़ताल

सी आई टी यू वर्किंग कमेटी द्वारा मजदूर वर्ग की चौतरफा लामबंदी करने का आह्वान

□ पी के गांगुली

दिल्ली में 27 से 29 जुलाई तक हुई, सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की बैठक ने 29 सितंबर की देशव्यापी आम हड़ताल को शानदार ढंग से सफल बनाने के लिए, मजदूरों के सभी तबकों की चौतरफा गोलबंदी का आह्वान किया है। नरसिंह राव सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान, 21 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न जनसंगठनों की राष्ट्रीय कन्वेंशन में किया गया था।

वर्किंग कमेटी की बैठक में, ई बालानंदन के अध्यक्षीय भाषण और फिर महासचिव एम के पंथे द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट ने ही बहस की दिशा तय कर दी और देशव्यापी जन-कार्रवाईयों की विचार के केंद्र में लेा दिया, था, जो 29 सितंबर की देशव्यापी हड़ताल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचेंगी।

रिपोर्ट पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने भी ट्रेड यूनियनों तथा किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं आदि अन्य तबकों के जन-संगठनों की विकसित होती जन-कार्रवाईयों पर और 29 सितंबर की हड़ताल से पहले अनेक कार्यक्रमों के लिये उनकी तैयारियों पर भी, विस्तार से रोशनी डाली।

ई बालानंदन के सी आइ टी यू का झंडा फहराने और शहीद स्तंभ पर फूलमालाएं चढ़ाकर शहीदों को याद किये जाने के साथ 27 जुलाई की सुबह बैठक शुरू हुई। बैठक की कार्रवाई के शुरू में ही दो बैठकों के बीच अंतरों में नहीं रहे नेताओं तथा साधियों को शोक प्रस्ताव स्वीकार कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

अध्यक्षीय भाषण

ई बालानंदन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में तमाम विकसित पूंजीवादी देशों में विगड़ती आर्थिक स्थितियों की ओर ध्यान खींचा और इसकी ओर भी ध्यान खींचा कि तथाकथित बाजार की अर्थव्यवस्था के नाम पर अर्थ

पूंजीवाद के रास्ते पर चल रहे तमाम भूतपूर्व समाजवादी देशों में हालात बद से बदतर हो गए हैं और ये देश बढ़ती बेकारी, मिल बंदियों, महंगाई और नकारात्मक विकास दर की आंधी में फँस गये हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अपने आर्थिक हालात में इस भारी गिरावट के चलते, जहां विकसित पूंजीवादी देशों के आपसी अंतर्विरोध तोड़े हुए हैं, वहीं ये देश आइ एम एफ तथा विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं तथा उनकी शर्तों के जरिए और गैट के जरिए, अपने संकट का बोझ भारी पैमाने पर, भारत समेत तीसरी दुनिया के देशों के कंधों पर डालने में कामयाब रहे हैं। सी आइ टी यू अध्यक्ष ने कहा कि विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की आज पूरी कोशिश ही यह है कि तीसरी दुनिया के देशों के साधनों को लूटा जाय और इन साधनों को आपस में बांट लिया जाय तथा इस तरह इन देशों को एक तरह से फिर से अपना उपनिवेश बना लिया जाय।

सी आइ टी यू अध्यक्ष ने ध्यान दिलाया कि भारत, अपने विशाल साधनों के साथ और अपने उन्नत घरेलू प्रौद्योगिकीय आधार के चलते, इस तरह को लूट का खास निशाना बना हुआ है। सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम करने के इरादे से संचालित अमरीकी साम्राज्यवाद, स्वाभाविक रूप से इस मुहिम का सरगना है। बालानंदन ने बताया कि किस तरह रीढ़विहीन राव सरकार एक-एक करके आइ एम एफ तथा विश्व बैंक के तमाम राष्ट्रविरोधी व जनविरोधी नुस्खों को स्वीकार करती रही थी और यह प्रक्रिया अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची है, अन्यायपूर्ण गैट समझौते में, जिसके जरिए देश को संप्रभुता ही साम्राज्यवादियों के हाथों गिरवी रख दी गयी है। सी आइ टी यू अध्यक्ष का कहना था कि देश में बढ़ते जन-संघर्षों ने सरकार को अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक पुनर्गठन करने के सरकार के अभियान को किसी हद तक धीमा जरूर किया है, लेकिन इन साम्राज्यवादी एजेंसियों के प्रति सरकार की

29 सितंबर की हड़ताल सफल बनाओ !

यफादारी अब भी कायम है और उसे गैट पर दस्तखत करने से भी नहीं रोका जा सका है। बहरहाल, सरकार जिस तरह अपने आपसमर्पण को उचित ठहराने की कोशिश कर रही है, उससे जाहिर है कि उसे बचाव की मुद्रा अपनाकर जनता के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। बहरहाल, सरकार को अपना विनाशकारी रास्ता छोड़ने पर मजबूर करने का एक ही तरीका है, जुझारू संघर्षों को और तेज किया जाय। इस सिलसिले में बालानंदन ने चामपंधी पार्टियों द्वारा छेड़े जा रहे नागरिक अवज्ञा आंदोलन तथा जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच द्वारा तैयार किये गये कार्रवाई के कार्यक्रमों का जिम्मा किया और इन कार्यक्रमों में जबर्दस्त ढंग से मजदूरों को उतारने का और 29 सितंबर की हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का आह्वान किया।

महासचिव की रिपोर्ट

सी आइ टी यू महासचिव, एम के पंधे द्वारा बैठक के सामने पेश की गयी रिपोर्ट में आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के पालन के विभिन्न पहलुओं के लागू किये जाने के परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने, पुनर्गठन की प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसके जरिए कदम दर कदम सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट किया जा रहा है और निजीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। सी आइ टी यू महासचिव ने ध्यान दिलाया कि यह निजीकरण जिसका सार उदारीकरण तथा वैश्वीकरण है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हरेक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों की घुसपैठ का रास्ता तैयार कर रहा है, भले ही संगठित युनियनादी उद्योगों का क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाइयों को जान-बूझकर बीमार बनाया जा रहा है तथा खत्म करने के इरादे से बी आइ एफ आर के हवाले किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुनाफ़ादेह इकाइयों की हिस्सा पूंजी को एक नीति के तहत पर निजी हाथों में बेचा जा रहा है। सीटू महासचिव ने कहा कि बढ़ती मिलबंदियों तथा बढ़ती बेरोजगारी सीधे-सीधे इसी नीति का नतीजा है और यही पुनर्गठन की प्रक्रिया का असली मकसद है। उन्होंने कहा कि इसी नीतियों का एक और प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि, मुद्रास्फीति दो अंकों में चल रही है और सोधे-समझे ढंग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तोड़ा जा रहा है, जिसका आम लोगों पर भारी बोझ पड़ रहा है। महासचिव की रिपोर्ट में तथ्य तथा आँकड़े देकर यह भी दिखाया गया कि किस तरह, बढ़ते विदेशी निवेश के बावजूद अर्थव्यवस्था में गतिरोध ही बना रहा है।

रिपोर्ट में 5 अप्रैल के संसद मार्च की समीक्षा की गयी और इसे मेहनतकशों के सभी तबकों और इन नीतियों की चपेट में आये आम जनता के सभी तबकों मसलन मजदूर, किसान, खेत मजदूर, छात्र, युवा, महिला आदि के बढ़ते असंतोष का संकेत माना गया और रेखांकित किया गया कि इस कार्रवाई ने सरकार की मौजूदा नीतियों को पलटने के लिए इन सभी तबकों के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। इस रैली के बाद, विभिन्न उद्योगों तथा उद्योग के क्षेत्रों में छेड़े गये विभिन्न जनसंगठनों का और मौजूदा नीतियों के खिलाफ कायम हो रही उद्योगवार एकता इस प्रक्रिया में कई मामलों में इंटर तथा बी एम एस के भी उद्योगवार कार्रवाइयों में शामिल होने पर मजबूर होने की ओर भी, रिपोर्ट में ध्यान खींचा गया।

रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र की 14 जुलाई की हड़ताल की भी समीक्षा की गयी जो इंटर द्वारा आखिरी वक्ता पर विश्वासघाती ढंग से अपने हाथ पीछे खींच लिये जाने के बावजूद, खासतौर पर कोयला उद्योग समेत अनेक उद्योगों में जबर्दस्त ढंग से सफल रही। रिपोर्ट में इसको के निजीकरण के खिलाफ एकजुट हड़ताल के आह्वान किया गया, जिसमें इंटर ने भी हिस्सा लिया था और जिस हड़ताल के बल पर इसको के निजीकरण की सरकार की कोशिश को टाला जा सका है।

रिपोर्ट में, असंगठित क्षेत्र में सी आइ टी यू द्वारा छेड़े गये संघर्ष की भी चर्चा की गयी और इस क्षेत्र में भी अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ एकता को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम गिलों के संबंध में हुए समझौते को लागू कराने के लिये संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

रिपोर्ट में, सी आइ टी यू द्वारा स्वीकृत सांगठनिक रिपोर्ट के पालन की विस्तार से समीक्षा की गयी और संगठन को, उसके जनतांत्रिक ढंग से काम-काज, सदस्यता आदि के लिहाज से और शक्तिशाली बनने और आंदोलनों को आगे बढ़ाने के, दोहरे काम को पूरा करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही, ट्रेड यूनियन एकता के प्रश्न पर अभियान चलाने तथा कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने का आह्वान किया गया, जिस प्रक्रिया को अंततः ट्रेड यूनियनों के परिसंघ के गठन में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना है।

रिपोर्ट में बी टी आर स्मारक ट्रस्ट के लिये एक दिन का येतन चंदे के रूप में देने का अभियान तेज करने का आग्रह किया गया। यह अभियान, कामरेड बी टी आर के नव्वेवें जन्म दिन, 19 दिसंबर 1994 तक पूरा हो जाना है। इसके साथ ही रिपोर्ट में सी आइ टी यू के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी ज्यौर दिया गया। रिपोर्ट में याद दिलाया गया कि अगले वर्ष तीस मई की, सी आइ टी यू के गठन के पच्चीस वर्ष पूरे हो रहे हैं और सी आइ टी यू की स्थापना की रजत जयंती उपायुक्त ढंग से मनाने का आह्वान किया गया।

रिपोर्ट में तय किये गये फौरी कामों में, 21 जून की कन्वेंशन में तय किये गये कार्रवाई के हरेक कार्यक्रम के लिये ठोस कार्ययोजनाएँ तैयार करने पर विस्तार से विचार करने का आह्वान किया गया। कन्वेंशन द्वारा तय किये गये कार्यक्रमों में, 3 से 9 अगस्त तक जन-अभियान सप्ताह का पालन, बीस सितंबर को अखिल भारतीय पैमाने पर "रेल रोको" कार्यक्रम, 27 सितंबर को मशाल जुलूस कार्यक्रम और 29 सितंबर को देशव्यापी आम हड़ताल, के आयोजन शामिल हैं। इस सिलसिले में तमाम अन्य जनसंगठनों के साथ और ज्यादा एकता कायम करते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया गया।

सरोज चौधरी ने बैठक में कोषाध्यक्ष के नाते अपनी रिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट पर बहस

महासचिव की रिपोर्ट पर वर्किंग कमिटी की बैठक में जीवंत बहस हुई। बहस में, आम तौर पर रिपोर्ट को तो लिया ही गया इसके अलावा, संघर्ष के कार्यक्रम के पालन और संगठन से संबंधित सवालों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर पचास वर्किंग कमिटी सदस्यों ने रिपोर्ट के इन तीनों पहलुओं पर अलग-अलग हुई बहस में हिस्सा लिया,

(पेज आठ पर)

वर्किंग कमेटी बैठक 24-26 जुलाई 1994, नयी दिल्ली

अध्यक्षीय भाषण

□ ई० बालानंदन

प्रिय साथियों,

इससे पूर्व कि मैं अपना अध्यक्षीय भाषण दूँ, आईये हम सब मिल कर विश्व में मजदूर वर्ग के दो महान नेताओं को अपने श्रद्धासुमन भेंट करें जो हमारे आठवें महाधिवेशन के पश्चात हमें विच्छेद दे गए हैं। कामरेड एरिक होनेकर-एक उत्कृष्ट क्रांतिकारी जिन्होंने अनेक वर्षों तक जर्मन समाजवादी लोक गणराज्य की बागडोर सम्भाली थी, का 29 मई 1994 को निधन हो गया। अपने जीवन के अंतिम समय वह चिल्ली में थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरम्भ नाजी विरोधी जुझारू के रूप में किया और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद की पराजय तक वह उसके विरुद्ध संघर्षरत रहे। वह जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने और उसके पश्चात् उन्हें सरकार का मुखिया भी बना दिया गया। इन दोनों पदों पर काम करते समय वह बहुत सीमा तक पूर्वी जर्मनी में समाजवाद का निर्माण करने में सफल रहे। बर्लिन की दीवार के ढह जाने तथा अपनी सरकार के अपदस्थ किये जाने पर भी कामरेड होनेकर ने अपनी राजनीतिक अवधारणाओं को नहीं बदला था और वह मजदूर वर्ग के हितों एवं लक्ष्यों के प्रति दृढ़तापूर्वक डटे रहे। उन्होंने जर्मनी के नए शासकों के आगे झुकने से इन्कार कर दिया। उन पर झूठे एवं मनघड़त आरोप लगाए गए और रूस से वापिस लाने के पश्चात् उन पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि उस समय वह गम्भीर रूप से बीमार थे। मुकदमे के समय अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर देते हुए अदालत में उन्होंने गर्जना की थी कि गैर कानूनी ढंग से बर्लिन की दीवार फांदने वाले लोगों को रोक कर उन्होंने अपने कर्तव्यों तथा कानूनी उत्तरदायित्वों का पालन ही किया था। आईये, हम उन्हें अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करें।

कामरेड किम इल सुंग का अचानक 8 जुलाई, 1994 को थॉंगयांग में दिल का दौरा पड़ने के कारण देहावसान हो गया। कामरेड किम इल सुंग जन्मजात क्रांतिकारी थे। उन्होंने जापानी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध कोरियाई जनता के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और जापानी साम्राज्यवादी की पराजय के पश्चात् वह कोरिया जनवादी लोक गणराज्य के राष्ट्रपति बने तथा जीवनपर्यंत इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में कोरिया जनवादी लोक गणराज्य में समाजवाद का निर्माण हुआ और जनता के समृद्ध जीवन को सुनिश्चित बनाया गया। अमरीकी साम्राज्यवादियों को भी 1952-53 के युद्ध में जब उन्होंने हस्तक्षेप किया था, पराजय का मुंह देखना पड़ा था।

एक नन्हा सा राष्ट्र भी यदि अपनी जनता तथा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को लामबंद कर लेता है तो वह अमरीकी साम्राज्यवाद को धूल चटा सकता है और सचमुच ही यह घटना विश्व भर को चौंका देने वाली

थी। देर या सवेर वह अमरीकी साम्राज्यवादियों के उस षडयंत्र को भी विफल बना देगा जिसके अन्तर्गत वे उत्तरी कोरिया की नाभिकीय क्षमताओं पर अंकुश (प्रतिबंध) लगाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उत्तरी कोरिया द्वारा चीन की सहायता से दृढ़तापूर्ण रुख अपनाए जाने के कारण अमरीकियों को अपना रुख बदलना पड़ा है। (मैं इस विषय पर बाद में अलग से अपने विचार व्यक्त करूंगा)। सोवियत संघ तथा पूर्व समाजवादी युरोपीय देशों में समाजवाद को लगे धक्के भी उसे समाजवाद के निर्माण के क्रांतिकारी पथ पर चलने से रोक नहीं सके हैं। कामरेड किम इल सुंग हमारे मध्य नहीं रहे। आईये, हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें तथा उत्तरी कोरिया की सरकार एवं जनता के प्रति समाजवाद को और सुदृढ़ बनाने के उनके कठिन संघर्ष की सफलता के लिये कामना करें।

आईये, हम अपने उन अनेक साथियों का स्मरण भी करें जो इस अवधि में हमें विच्छेद दे गए हैं। आईये, हम उनके लक्ष्य की प्राप्ति तथा समाजवाद की स्थापना हेतु संघर्ष जारी रखने का प्रण करें।

आठवें महाधिवेशन के बाद की अवधि सी आई टी यू के लिए भारी गतिविधियों की अवधि रही है। महासचिव की रिपोर्ट में उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। मैं स्वयं को आपके समक्ष कुछ मुद्दे प्रस्तुत करने तक ही सीमित रखूंगा।

साथियों, हमारे महाधिवेशन के पश्चात् एक महान एवं उल्लेखनीय घटना घटित हुई है। दक्षिण अफ्रीका में नये लोकतांत्रिक संविधान के अन्तर्गत जिसमें श्वेत एवं अश्वेत लोगों को एक समान मताधिकार प्रदान किया गया है, हुए चुनावों में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के साम्राज्यवाद जिसमें रंगभेद की घुणित व्यवस्था भी सम्मिलित है, को दफन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के किंवदन्ती नेता डाक्टर नेलसन मंडेला 10 मई, 1994 को अपने देश के राष्ट्रपति बन गए। यह एक ऐतिहासिक घटना है, इसमें संदेह नहीं। कुल 2 करोड़ बीस लाख मतदाताओं में से 65 प्रतिशत ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में अपना मत दिया। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस न केवल विभिन्न समूहों को चुनावों में भाग लेने के लिये तैयार कर सकी अपितु वह ऐसी सरकार की स्थापना करने में भी सफल रही है जिसमें सभी राजनीतिक दलों तथा जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यद्यपि एकता स्थापित की जा चुकी है और संयुक्त टीमा ने देश की सत्ता को सम्भाल लिया है तथापि अभी भी सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी अपनी संकीर्ण प्राथमिकताएं तथा लक्ष्य हैं। सरकार के सुचारु संचालन में इसके कारण व्यावधान उत्पन्न हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका की जनता विशेष रूप से दो करोड़ सतर लाख अश्वेत जिनके

साथ रंगभेदी व्यवस्था के समय पिछली अनेक शताब्दियों में अमानवीय व्यवहार हुआ है, अपनी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान निकाले जाने की अपेक्षाएं रखते हैं और सरकार पर उनकी भारी आशाएं हैं। उनकी भारी आवश्यकताएं रोजगार, खुराक, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल इत्यादि की हैं। अच्छा जीवन बिताने वाले श्वेत अपनी सुविधाओं को जितने वे अब तक भोगते रहे हैं। पूर्वतः बनाए रखना और उनमें सुधार लाना चाहते हैं। नेलसन मंडेला की सरकार को ऐसी ही भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कार्य अत्यंत कठिन है।

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित सरकार का अस्तित्व में आना अपने में एक महान घटना है। उनके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं वे विश्व में सोने के सबसे बड़े उत्पादक हैं और प्लैटिनम एवं डायमंड के उत्पादन में उनका दूसरा तथा युरेनियम के उत्पादन में तीसरा स्थान है। और अब तो उन्होंने अपतटीय (समुद्र से) तेल का भी पता लगा लिया है। इसके साथ-साथ यदि मानव संसाधनों का भी समुचित उपयोग किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र का एक ऐसा सुदृढ़ राष्ट्र बना सकता है जो निश्चित रूप से लोकतंत्र की सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान डाल सकता है।

सी आइ टी यू तथा भारत की ट्रेड यूनियन देश की जनता के साथ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के शानदार स्वतंत्रता संघर्ष में उसके पक्ष में खड़ी रही हैं। इस महान संघर्ष में दक्षिण अफ्रीका की ट्रेड यूनियन, सी ओ एस ए टी यू तथा दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी भी प्रमुख भागीदार थीं। सी आइ टी यू ने इस संघर्ष के लिये वित्तीय सहायता जुटाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। अतः हम विश्व की अन्य लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की विजय पर गौरवान्वित होने के अधिकारी हैं। एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका निश्चित रूप से अफ्रीकी महाद्वीप की काया पलट देगा। साथियों, आपकी अनुमति से मैं दक्षिण अफ्रीका की नया रंगभेद रहित लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्यम की सफलता के लिए कामना करता हूँ।

अमरीका को उत्तरी कोरिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी अपने कृपयास रोक देने पड़े हैं। वह चाहता था कि उत्तरी कोरिया अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने नाभिकीय टिकाओं की जांच करने तथा उन्हें समाप्त करने की अनुमति दे। उत्तरी कोरिया ने अमरीकी संकेतों पर नाचने से इन्कार कर दिया। वह (उत्तरी कोरिया) चीन तथा दूसरे देशों जिनमें रूस भी शामिल है, की सहायता से अपने रुख पर दृढ़ रहा। उसने घोषणा की कि यदि आइ ए इ ए कोरिया के नाभिकीय कार्यक्रमों के लिए सहायता नहीं देती तो वह उससे बाहर आ जाएगा। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र को डाल बना कर उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली और उसे तुरंत पीछे हटना पड़ा।

उन्होंने चीन को भी धमकाने का प्रयास किया और यहां तक कह दिया कि वे तथाकथित मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उसे अत्यंत विशिष्ट देश का दिया गया दर्जा समाप्त कर देंगे। किन्तु चीन ने इसका करार प्रत्युत्तर दिया। उसने कहा कि यह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और यह इस प्रश्न पर अमरीकी सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। अन्ततः अमरीका के बड़े व्यावसायिक गृहों ने श्री क्लिंटन

पर दबाव डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में अमरीका बाजी हार जाएगा। इसलिए चीन को अत्यंत विशिष्ट राष्ट्र का जो दर्जा दिया गया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और यहां भी अमरीका को पीछे हटने पर विचार होना पड़ा।

मैं आर्थिक मोर्चे पर घटने की वाली घटनाओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित अन्य घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मई में जारी 'विश्व का आर्थिक दृष्टिकोण' में बताया गया है कि वर्ष 1994 तथा 1995 में विश्व उत्पादन क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत होगा। अमरीका के मामले में उन्होंने वर्ष 1993 में 3 प्रतिशत विकास दर प्राप्त की थी। उसके 1994 में बढ़ कर 3.9 प्रतिशत तक पहुंच जाने की बात कही गई और यह भी बताया गया कि 1995 में वह कम होकर 2.6 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाएगा। कैनेडा के लिये विकास दरें क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत, युनाइटेड किंगडम के लिए 1.9 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत बताई गई हैं। युरोप महाद्वीप तथा जापान अब अपने गंदे के निचले स्तर तक पहुंच गए हैं। जापान और जर्मनी के मामले में विकास दरें 0.7 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत तथा 2.1 प्रतिशत और समूचे तौर पर युरोप के लिये 0.9 प्रतिशत तथा 1.3 से 2.5 प्रतिशत हैं।

ओ ई सी डी जो विश्व के 25 विकसित देशों पर आधारित हैं, के द्वारा विकास की दर के सम्बन्ध में एक परियोजना के अन्तर्गत काम कराया गया है। इसके निष्कर्षों के प्रति सतर्कता व्यक्त करते हुए इन देशों में कुछ सीमा तक इसे आशावादी माना है। विश्व की वास्तविक विकास दर जो निकाली गई है, से पता चलता है कि एशियाई देशों में भी भारी विकास दर वाले क्षेत्र हैं। अनेक देशों की विकास दर अभी भी कम है। परेशान करने वाली बात तो यह है कि यह विकास दर रोजगार वृद्धि की ओर संकेत नहीं करती और विकसित देशों जिन्हें उच्च प्रौद्योगिकी वाले देश कहा जाता है, में बेरोजगारी तथा जनता के कष्टों में वृद्धि होती चली जा रही है।

सरकारी अनुमानों के अनुसार आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ ई सी डी) के देशों में कुछ सुधार होने पर भी साढ़े तीन करोड़ लोग 1993 में बेरोजगार थे जो कुल श्रम शक्ति का 8.5% बने हैं। मई में प्रकाशित 'इकॉनॉमिक आउटलुक' के अनुसार युरोपीय देशों में बेरोजगारी की वर्तमान दर 1960 वें तथा 1970 वें दशक की दर की अपेक्षा 4 गुणा अधिक थी। युरोपीय भाईचारे के देशों में बेरोजगारी की दर 1993 में 10.5 प्रतिशत थी और 1994 में भी यही दर बनी रहेगी। अमरीका में बेरोजगारी की सरकारी दर 6.4% है।

इन सभी देशों में अंशकालिक रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उन्हें रोजगार प्राप्त माना जाता है। यदि इसकी गणना भी की जाए तो युरोप में बेरोजगारी की दर 12.5% या 5 करोड़ व्यक्ति हो जाएगी। अमरीका में बेरोजगारी का वर्तमान अनुपात 6.4% बढ़कर 9.3%, ब्रिटेन में 9.8% की अपेक्षा 12.3% हो जाएगा। जापान में सरकारी तौर पर घोषित बेरोजगारी की दर 2.7% बढ़कर 9.60 हो जाएगी।

जापान में दूसरे किसी भी देश की अपेक्षा अधिक लोग अंशकालिक रोजगार पर लगे हुए हैं। ओ ई सी डी के अनेक देशों में 2 से 3 प्रतिशत बेरोजगारों के नाम बेरोजगारी के रजिस्टर में दर्ज नहीं किये जाते क्योंकि

वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं या कुछ बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। यूरोप में अधिकांश बेरोजगारों को पिछले 12 महीनों से काम नहीं मिला है। ये बेरोजगार 25 से 44 वर्ष की आयु समूह के हैं।

असंक्रालिक काम पर लगे लोगों में भारी संख्या महिलाओं की है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है बेरोजगारी की समस्या अत्यंत विकट रूप धारण कर चुकी है। यह समस्या 'रोजगार विहीन विकास' की तथाकथित नीति के कारण और भी गम्भीर रूप धारण कर रही है। मैं इस समय पूर्व समाजवादी देशों विशेष रूप से रूस की स्थिति का वर्णन नहीं करूंगा जहां बेरोजगारी तथा जनता के कष्टों में विनाशकारी सीमा तक वृद्धि हो रही है।

बेरोजगारी की समस्या के लिये जो निदान सुझाया जा रहा है वह उसके रोग से भी बुरा है। सरकारी नेताओं ने हाल ही में इस विषय पर विचार किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को पहलकदमी पर जून, 1994 डेट्रायट में शिक्षा वार्ता हुई थी। ओ इ सी डी की एक समिति ने इस समस्या पर विचार किया था और बेरोजगारी पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया। इन सभी विचार विमर्शों तथा अध्ययनों के फलस्वरूप संगठन के देशों ने एक-दूसरे के विपरीत रुख अपना लिये। इन सभी बहसों में यूरोप तथा अमरीका में श्रमिकों की स्थिति की तुलना की गई और सामान्य रूप से अमरीकी माडल को स्वीकार कर लिया गया। अमरीका माडल में बेरोजगारों के लिए कम लाभ सुझाए गए थे।

अमरीका में बेरोजगारी के आंकड़े वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करते। इसका कारण वहां वेंतनों में भारी असमानता का होना है। अमरीका की जनसंख्या का 14 प्रतिशत भाग या साढ़े तीन करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। जर्मनी की तुलना में वहां कार्यकारी [एजीफ़्टिव] अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के वेतन अत्यधिक हैं और श्रमिकों के वेतन बहुत ही कम। हैराल्ड इंटरनेशनल ट्रिब्यून के 8-7-94 के अंक में अमरीका में आय की असमानता को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

“सभी समुद्र लोकतंत्रों में अमरीका ही केवल एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले दशक में आय की असमानता तेजी के साथ बढ़ी है और गरीब मजदूरों के वेतन नीचे सरके हैं। अनेक अमरीकियों की आय में भारी लाभ (वृद्धि) हुए हैं, किन्तु ये अधिकांश लाभ सर्वाधिक समृद्ध लोगों जो देश की जनसंख्या का पंचम भाग हैं, तक ही केन्द्रित रहे हैं।”

अमरीका में यूनियनों की सदस्य संख्या में भारी कमी भारी विषमताओं से उत्पन्न एक और कारक है:”

उसने अपना तर्क जारी रखते हुए कहा है: “नये रोजगार उत्पन्न करने के मामले में कोई हस्तक्षेप किये बिना असमानता में वृद्धि को रोकने और निचले स्तर पर रह रहे लोगों की धीरे दूरदरा को दलदल में न जाने देने के लिये हमें विधियों की खोज करनी पड़ेगी। जब श्रीमती का निदान अधिक खर्चीला हो जाता है तब उसके विकल्प के विषय पर विचार करना बुद्धिमत्तापूर्ण होता है: और वही भी ऐसे देश में जहां अमीर और गरीब में अन्तर बढ़ता चला जा रहा हो, वर्गीय शत्रुता तथा असंतोष की राजनीति का स्वर तीखा होता चला जा रहा हो।”

उपरोक्त उवाच से स्पष्ट हो जाता है कि विकसित पूंजीवादी समाजों

में बेरोजगारी तथा दरिद्रता में वृद्धि हो रही है जिससे विभिन्न प्रकार के सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। पूंजीवाद ही “मानवीय प्रगति का एकमात्र मार्ग है,” ऐसे लम्बे-चौड़े दावे उन तथ्यों से मेल नहीं खाते जो यह दर्शाते हैं कि पूंजीवाद जनसंख्या की भारी बहुसंख्या के लिये असमानता तथा दरिद्रता में वृद्धि करेगा।

भारत की आर्थिक स्थिति पर यहां बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने अपने पटना महाधिवेशन में इस पर सविस्तार चर्चा की थी। मैं केवल उन्हीं विशेष मुद्दों को उठाना चाहूंगा जो हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाप्त कर रहे हैं। तथापि मुझे ‘द इकनामिक टाइम्स’ के दिनांक 22 जुलाई, 94 के अंक में प्रकाशित एक लेख का छोटा सा उद्धरण देने की अनुमति दी जाए। उसका शीर्षक है—अन इम्प्लायमेंट: लैसन्स फ्राम यूरोप (बेरोजगारी: यूरोप के कुछ सबक)। उसमें कहा गया है, “भारत में भी उत्पाद वृद्धि से रोजगार नहीं बढ़ता। 1980 के दशक का अनुभव हमारे सामने है। तब उत्पादन में अत्यंत पूर्व वृद्धि (3.5 प्रतिशत से बढ़ कर 5.3 प्रतिशत) हुई थी किन्तु रोजगार की दर में विनाशकारी सीमा तक कमी (2.8 से कम होकर 1.5 प्रतिशत) हुई थी। यह संकेत चौंका देने वाला है। यह विकास तथा रोजगार सर्जन में विषमता लाता है और भारत को इसी संकेत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नीति निर्धारक भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते समय इन आंकड़ों का प्रयोग नहीं करते।”

हमारे देश के लोग अब आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों तथा सेवाओं में दैनंदिन वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के कुप्रभावों को अनुभव करने लगे हैं। नयी नीति के एक भाग के रूप में जन वितरण प्रणाली को भंग करने की प्रक्रिया जारी है। खुले बाजार में 1991 से 1994 तक गेहूं और चावल के खुदरा मूल्य 75% से अधिक बढ़ चुके हैं। चीनी का मूल्य 9 रुपए से बढ़ कर 18 रुपए हो गया है। कुछ सीमा तक जन वितरण प्रणाली के लिए चीनी के कोटे में कमी किये जाने जिसे 31% से कम करके 13% कर दिया गया है, के कारण मूल्य वृद्धि हुई है, दूसरे इस पर लगे नियंत्रण पर ढोल दी गई है। दैनंदिन उपभोग की लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य असहनीय सीमा तक बढ़ चुके हैं। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य भी बढ़ गए हैं। सरकारी मूल्य सूचकांक 12% तक ऊपर चला गया है। इन सभी बातों को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम पर न्यायोचित ठहराया जा रहा है। इसका परिणाम यह निकला है कि हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को असहनीय कठिनाईयों से दो-चार होना पड़ रहा है। मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हमारी जनसंख्या के बड़े से बड़े भाग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ हैं।

बिजली, पानी, उर्वरक इत्यादि पर सब्सिडी में कटौती किये जाने सम्बन्धी नयी नीति के कारण हमारे कृषि उत्पादन पर विषम प्रभाव पड़ा है।

बहुराष्ट्रीयों को ऊर्जा, तेल, कोयला, बैंकिंग, बीमा, नागरिक उड्डयन तथा टेलीकाम जैसे हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्रों में घुसने की छूट देकर देश की बर्बादी को न्यौता दे दिया गया है। ये वही क्षेत्र हैं जहां हमने पर्याप्त प्रगति की है और हम विदेशी कम्पनियों से होड़ लेने

की स्थिति में हैं। हमारे देश में बिजली और तेल की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय लागत का केवल एक तिहाई भाग है। ऊर्जा की कम लागत हमें बाजार की प्रतिस्पर्धा में उतारने में सहायता देगी। विदेशी कम्पनियों इसी लाभप्रद स्थिति का प्रयोग अपने हितों के लिये करना चाहती हैं।

नवीनतम रिपोर्ट यह है कि अमरीका की ऊर्जा मंत्री ने बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कम्पनियों के अपने दल के साथ हमारे ऊर्जा मंत्री से बातचीत की और वह भारत में 25000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने के लिये 75 हजार करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश ऊर्जा क्षेत्र में करने को तैयार हो गई। एक बड़ी घटना कह कर इसका स्वागत किया जा रहा है। कहा जाता है कि भारत सरकार ने 16 प्रतिशत लाभ देने की उनकी मांग स्वीकार कर ली है और इसके लिये उसे गारंटी भी दी गई है। एनरोन प्रोजेक्ट, बम्बई के मामले में भी भारत सरकार कुछ ऐसा ही करने पर सहमत हुई है। हमारे विशेषज्ञों ने इसके दुष्परिणामों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि इसके परिणामस्वरूप देश में बिजली का मूल्य उछल कर 4 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा जबकि इस समय वह 1.18 रुपए से 1.50 रुपए के मध्य है। यदि इस नीति को पावर इंजीनियरिंग उद्योग में जारी रहने दिया गया तो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की एक और बड़ी कम्पनी जो कम लागत पर विश्व स्तर की पावर मशीनें बना सकती है और लगभग सभी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करती है, की कार्यक्षमता के अभाव से रूत होना पड़ेगा। यही नहीं, अब तक इस उद्योग में हमने जिस प्रौद्योगिकी को विकसित किया है, वह बर्बाद हो जाएगी। ऊर्जा की अधिक लागत होने के कारण वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और इसका हमारे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके दुष्परिणामस्वरूप अ-उद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तेल के मामले में भी यही स्थिति है।

तेल क्षेत्र में भारत सरकार स्वदेशी उत्पादन में सुधार लाने की अपेक्षा बहुराष्ट्रीयों को घुसपैठ करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है। स्वदेशी कच्चे तेल की उत्पादन लागत तथा आयातित कच्चे तेल के मूल्यों का पिछले पांच वर्ष का विवरण नीचे दिया जा रहा है। हमारे कच्चे तेल की लागत में तैल सैस, रायल्टी तथा कर इत्यादि भी शामिल किये गए हैं अन्यथा यह लगभग 1500 रुपए प्रति टन बैठता है।

अवधि	आयातित तेल	स्वदेशी तेल
1989-90	3189.68	22.69.12
1990-91	4447.15	2442.80
1991-92	4735.08	2442.80
1992-93	5137.83	
1993-94	5145.61	3295.76

सरकार अपनी इस नीति के पक्ष में केवल एक तर्क वित्तीय संकट का ही देती है। यदि भारत की ऊर्जा उत्पादक इकाइयों, विद्युत बोर्डों के केंद्रीय उपक्रमों तथा ओ एन जी सी को अपनी लागत में मामूली वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की जाए तो ये बड़ी आसानी से इन क्षेत्रों के

विकास के लिए संसाधन जुटा सकते हैं। यहां में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्योगों पर नयी नीतियों के प्रभाव के अन्य विवरणों में नहीं पढ़ेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र पर धावा बोलने के लिए सरकार तथा उसके प्रबन्धक सदा उसके कार्यप्रदर्शन की निंदा करते रहते हैं। उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 1992-93 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्योगों के सम्बन्ध में अपने वार्षिक सर्वेक्षण में सर्वथा भिन्न चित्र प्रस्तुत किया है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक उपक्रम विभाग की ओर से जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, "लाभदायकता, आंतरिक संसाधन जुटाने तथा अतिरिक्त मूल्य इत्यादि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र का भारी योगदान रहा है। 13.3 उद्योगों का पिछले दस वर्षों से कुल लाभ बढ़ता ही चला गया है, यह 1983-84 में 3761 करोड़ रुपए था और 1992-93 में बढ़ कर 25,217 करोड़ रुपए हो गया अर्थात् उनके लाभ में 36.94 प्रतिशत वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की 116 इकाइयों ने 1983-84 में 3,278 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधन जुटाए थे, जो 1991-92 में बढ़कर 12,943 करोड़ रुपए के हो गए, इस बार इन इकाइयों की संख्या 143 थी और 1992-93 में 146 इकाइयों ने 14,723 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधन जुटाए। सातवीं पंच वर्षीय योजना में सार्वजनिक उपक्रमों (उद्योगों) ने 37,677.71 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधन जुटाए थे। मैनुफैक्चरिंग उपक्रमों ने 1983-84 में अतिरिक्त दस हजार अड़तालीस करोड़ रुपए का लाभ कमाया, 1992-93 में यह बढ़ कर 13,150 करोड़ रुपए हो गया अर्थात् उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.24 प्रतिशत वृद्धि हुई।

बैंकिंग तथा बीमा उद्योग ने देश के योजनाबद्ध विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग तथा बीमा उद्योग ने औद्योगिक तथा कृषि विकास की आगे बढ़ाया है। कार्य कुशलता में सुधार के नाम पर "इन क्षेत्रों पर धावा बोला जा रहा है जो राष्ट्र हित में नहीं है।" हमारे साधारण बीमा की विकास दर विश्व भर में सर्वाधिक ऊंची है और उसके कार्य प्रदर्शन की उसके ग्राहकों की भारी संख्या ने सराहना की है। जीवन बीमा निगम ने राष्ट्रीय विकास की विभिन्न योजनाओं में सहायता 16 हजार करोड़ रुपए का योगदान डाला है।

इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र के निंदा अभियान का ट्रेड यूनियन आंदोलन को जनता के मध्य अपने प्रचार को बढ़ा कर करारा प्रत्युत्तर देना चाहिए। ट्रेड यूनियनों की सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार गोल करने और निजीकरण के प्रयासों के वास्तविक दुष्परभावों से जनता को अवगत करा कर उसे शिक्षित करना चाहिए। इसके लिये एक-एक केस को लिया जाना चाहिए।

गैट करार पर हस्ताक्षर करने के परचातु भारत सरकार बहुराष्ट्रीयों के साथ भारतीय पूंजीपतियों के समान व्यवहार कर रही है। अनेक मामलों में तो उससे भी "अधिक समान" व्यवहार कर रही है। यही कारण है कि देश के बड़े पूंजीपति अपने साथ "समान व्यवहार तथा एक समान समझने" की दुहाई देने लगे हैं। हम इसके एक और पोरशान करने वाले पक्ष को देख रहे हैं। अनेक बड़ी कम्पनियों जिनका अपने उत्पादों के कारण बड़ा नाम है, उन्होंने अपने उद्योगों में बहुत भारी लाभ अर्जित किया है, भी बड़े बहुराष्ट्रीयों के अपने क्षेत्र में उसे होड़ लेने के लिए उतरने पर भयभीत हैं। उनमें से अधिकांश उनके साथ होड़ न लेने की "बुद्धिमता"

दिखा रही हैं क्योंकि उनकी अपेक्षा बहुराष्ट्रीयों की वित्तीय शक्ति बहुत अधिक है, बाजार तक उनकी पहुंच भी उनसे कहीं अधिक है। इस स्थिति में उनमें से अनेक कम्पनियों तो भारी मूल्य लेकर अपने उद्योग बंद कर चुकी हैं और कुछ तो उनकी कनिष्ठ सहयोगी बन रही हैं। पारले, केल्वीनेटर, टोम्को, एच एम, डिनस क्लब, इस्कन, किसान इत्यादि की यही कहानी है। मैं इस पर और अधिक चर्चा नहीं करूंगा।

जैसा कि ऊपर रेखांकित किया जा चुका है, हमारे आठवें महाधिवेशन के पश्चात् सी आई टी यू भारी गतिविधियों में व्यस्त रही है। उनमें से कुछ गतिविधियों का उल्लेख मैं यहां करूंगा। जन संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों की ओर से 5 अप्रैल को दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जन संगठनों की भागीदारी और सुशासक भावना को प्रतिबिम्बित करने वाली यह एक विशिष्ट घटना थी। इससे भारत सरकार को जबरदस्त चेतावनी मिली कि मजदूर वर्ग तथा जनता सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों को सहन नहीं करेगी। ईटक की हिचकिचाहट और हड़ताल से पीछे हट जाने पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा 14 जुलाई को की गई हड़ताल सफल रही। 21 जून को दिल्ली में जन संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों का सम्मेलन भी अत्यधिक सफल रहा। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए जिनमें 29 सितंबर की आम हड़ताल का निर्णय भी शामिल है।

हमें इस तथ्य को भी रेखांकित करना होगा कि वाम दल सरकार की नीति के विरोध में 16 अगस्त से 9 सितंबर तक नागरिक अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में भी ट्रेड यूनियनों को समुचित ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करना है।

साथियों, हमारे महाधिवेशन के पश्चात् पिछले चार मास का अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में हमारी संगठनात्मक गतिविधियों में सुधार हुआ है। हमारा भाषण सम्पन्न करने से पूर्व मैं अनेक उद्योगों जिनमें से अधिकांश उद्योगों को बी आई एफ आर के हवाले किया जा रहा है, में बंद रही बीमारी के प्रश्न पर चर्चा करना चाहूंगा। बीमार उद्योगों की सूची और बढ़ गई है और सरकार अनेक क्षेत्रों में स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से निर्गम नीति को कार्यरूप दे रही है और हजारों मजदूरों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है।

हमें बड़े रोज औद्योगिक बीमारी से निपटने हेतु विशेष कदम उठाने होंगे। हम पहले ही इसे अपने आठवें महाधिवेशन में रेखांकित कर चुके हैं। हमने ट्रेड यूनियन एकता के लिए अपने सुझाव दिये हैं। "ट्रेड यूनियनों के परिषद" के सुझाव पर अनेक शर्तियां की गई हैं। यह एक स्वागत योग्य लक्षण है। हमें इस दिशा में और कदम उठाने होंगे और देखना होगा कि ट्रेड यूनियनों में लचकीले पग के साथ संगठनात्मक एकता लाई जाए।

साथियों, हमारा अनुभव दर्शाता है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के सम्पन्न में सरकार को अपनी अनेक नीतियों बदलने पर विवश कर सके हैं, हम उस पर संयुक्त रूप से पर्याप्त दबाव डाल सके हैं। इस्को का मामला एक ऐसा मामला है जहां हम सरकार को उसका निजीकरण करने सम्पन्न प्रस्ताव को वापस लेने पर विवश कर सके हैं। इस्को के निजीकरण के विरोध में आयोजित हड़ताल की संयुक्त कार्रवाई में ईटक भी शामिल हुई थी। संसद के भीतर तथा बाहर दोनों ओर संयुक्त प्रतिरोध होने के कारण सरकार ट्रेड यूनियन संरोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत

ही नहीं कर सकी। सार्वजनिक क्षेत्रों के अनेक मामलों में ऐसा हुआ है जहां सरकार को अपने सुझाव वापस लेने पड़े और श्रमिकों के संयुक्त प्रतिरोध के कारण उसे उनमें संरोधन करना पड़ा। हम सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन जाम करने के सिद्धांत का भी मुंह तोड़ उतर दे सके हैं। हमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी की नयी घोषणा को भी रेखांकित करना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमारी इकाइयों को जीवन-क्षम बनाने के लिये नया कोष स्थापित किया जा रहा है। इस घोषणा के विवरण पर गम्भीरता पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है। तथापि बीमार उद्योगों को बी आई एफ आर के पास भेजने के एकमात्र उपचार को अब अपर्याप्त माना जाने लगा है। ऐसा हमारे आंदोलन के दबाव के कारण ही हो सकता है। ऊर्जा, टेलीकाम, टेक्सटाइल, बैंकिंग, बीमा इत्यादि क्षेत्रों में सरकारी धावों के विरोध में संयुक्त आंदोलन विकसित हो रहा है। वित्तीय क्षेत्र में हड़ताल की अगली कार्रवाईयों पर विचार हो रहा है और टेलीकाम क्षेत्र निजीकरण के विरोध में हड़ताल करने का निर्णय लिया जा चुका है। ऊर्जा कर्मचारी तथा इंजीनियर पावर इंजीनियरिंग उद्योगों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संग सरकारी नीति के विरोध में संयुक्त कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कपड़ा उद्योग में संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की गई है। जिसमें ईटक भी शामिल है। संयुक्त संघर्ष समिति ने नवंबर में कपड़ा मजदूरों के संसद की कूच करने का निर्णय लिया है। यदि इन संयुक्त आंदोलनों को समुचित ढंग से सुदृढ़ बनाया जाता है और दूसरे सभी उद्योगों में आगे बढ़ाया जाता है तो मुझे विश्वास है कि न केवल इन उद्योगों से सम्बन्धित अपितु समूचे तौर सरकार की श्रमिक विरोधी नीति को चौपट किया जा सकता है। संगठित क्षेत्र में उद्योगों तथा रोजगार को सुरक्षार्थ संयुक्त आंदोलनों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ हमें असंगठित क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों को केन्द्रित करना होगा। हमें यह बात रेखांकित करनी होगी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नुस्त्ये वाली नयी औद्योगिक नीति के साथ सरकार अ-उद्योगीकरण के मार्ग पर चलने की तुली हुई है, वह संगठित क्षेत्र को कम करके देख रही है और असंगठित क्षेत्र में सामान तैयार करा रही है, इस प्रकार वह सस्ती मजदूरी का शोषण कर रही है। असंगठित क्षेत्र पर गठित अयोग तथा हाल ही में दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में इस प्रश्न पर विचार किया गया है। इसलिये असंगठित क्षेत्र में हमें योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा और स्थिति की मांग के अनुरूप आंदोलन चलाना होगा।

अंत में, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि कुछ समितियों द्वारा संगठनात्मक निर्देशों के गम्भीरतापूर्वक कार्यरूप नहीं दिया जा रहा है। सी आई टी यू बढ़ रहे संघर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके और आंदोलन को आगे बढ़ा सके, इसके लिये संगठन को सुदृढ़ बनाना एक अनिवार्य एवं पूर्व शर्त है। सी आई टी यू की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ-साथ हमारी संगठनात्मक स्थिति में भी सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं। इसके लिये समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

साथियों, आईये हम और बड़े एवं मजबूत संघर्षों की ओर कूच करें तथा 29 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल को जबरदस्त सफल बनाएं।

भुवनेश्वर में जनसंगठनों का राज्य सम्मेलन

जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच की उद्घोषा इकाई के आह्वान पर गत 17 जुलाई को भुवनेश्वर में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता शिवाजी पटनायक (एस एम एस), भगवान एम (एटक), गंगाधर पैकरे (उत्कल किसान सभा), उदुव जेना (के के एम एस), सुभाष सिंह (डी वॉई एफ आइ), तापसी प्रहाराज (ए आइ डी डब्ल्यू ए), छवि मोहंती (ए आइ डी एस ओ), सरोज दास (बी इ एफ आइ), किशोर जेना (ए आइ बी ए), योगीनाथ जेना (सैंट्रल मवर्नमेंट इम्प्लाइज फेडरेशन) तथा राधा नंदा राज्य स्तरीय समन्वय समिति पर आधारित अध्यक्षमंडल ने की।

सी आइ टी यू की उद्घोषा राज्य समिति के सचिव लम्बोदर नायक ने 21 जून को नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पारित प्रस्ताव के प्रकाश में 15 सूत्रीय प्रस्ताव का प्राप्ति तथा संघर्ष योजना प्रस्तुत की। प्रतिनिधियों द्वारा उस पर विचार किये जाने के पश्चात उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सम्मेलन में चार घण्टों तक बहस हुई जिसके फलस्वरूप प्रतिनिधियों में उत्साह का संचार हुआ। प्रवीर पलित (एटक), वैष्णव दास (एच एम एस), मायाधर नायक (यू टी यू सी-एल एस), जगन नाथ मिश्रा (उद्घोषा प्रशक सभा), सुरेश पाणिग्रही (एस एफ आइ),

सिसिर हुई (डी वॉई एफ आइ), छवि मोहंती (ए आइ डी एस ओ), कुमुदिनी बहेरा (ए आइ डी डब्ल्यू ए), सुरेश मोहंती (सी पी एस टी यू), एस के दास (ओ एस आर यू), क्षेत्र मोहन दास (राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति), लिली नंदा (एस एस एस), किशोर जेना (ए आइ बी इ ए), प्रदीप सादंगी (बी डी एफ आइ) भास्कर जेना (ए आइ डी वॉई ए), उदुव जेना (के के एम एस), राम चन्द्र नामक (एल आई सी कर्मचारी), वासुदेव समाल, दुमाना दास (साधारण बीमा कर्मचारी संगठन) तथा प्राइवेट कालेज टीचर्स एसोसिएशन के कामरेड सुरेन्द्र जेना इत्यादि प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया।

सम्मेलन में उद्घोषा में बाद की स्थिति पर विशेष प्रस्ताव पारित करके सरकार से बाद की रोकथाम का स्थायी प्रबंध करने की मांग की गई। यह प्रस्ताव गंगाधर पैकरे ने प्रस्तुत किया जबकि के के एम एस के उदुव जेना द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

कामरेड शिवाजी पटनायक ने समापन भाषण दिया। उन्होंने 29 सितम्बर की हड़ताल को सफल बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के निर्देशों पर अपनाई गई भारत सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने गैर करार पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार की कड़ी आलोचना की।

[पेज दो का लेख]

जिन साथियों ने बहस में हिस्सा लिया उनमें पद्मालोचन, एम राजन, के के विश्वाकर्षण, बी जी भास्कर नाथ, बी बी चौरयन (केरल), तंजारी चर्जी, देवांजन चक्रवर्ती, लक्ष्मण सेठ, सुखमय पाल, सुनील यमुने, तलित सेधवार, सोमन कुंड, प्रीतनर, काली घोष, [प. बंगाल], जे एस मजुमदार, के के विमली, एस के बखशी, रमणिका गुप्ता [विहार], आर सिंगलाल पैलू, डी ज्ञानकी रमण, एस के पदमनाभ, [तमिलनाडु] सत्यदे अहमद, के एल यनाज [महाराष्ट्र] विजय मिश्रा, रघुनाथ सिंह, बलवंत सिंह [पंजाब], एस कुमार [मध्य प्रदेश], सतबीर सिंह [हरियाणा], पी एस गुरेवाल, के एस तिवारी [दिल्ली] के केंद्रोदेशरघु, एन प्रसाद राव, पी बी रामोदरा, पी सत्यनारायण [आंध्र प्रदेश], विजय रावत [उत्तर प्रदेश], सुधीर मेहता [गुजरात], कामरौी ठाकुर [हिमाचल प्रदेश], रवींद्र मुक्तान [राजस्थान] तथा एस सुर्वनारायण राव [कर्नाटक] इत्यादि शामिल हैं।

विवक्ताओं ने, नई आर्थिक नीतियों को लागू किये जाने के अर्थव्यवस्था के विफलताओं में जो विनाशकारी परिणाम लाए हैं, उनके बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में फैली बीबंदी तथा मिलबंदियों के बारे में और बी आइ एफ आर की भूमिका के बारे में बर्षों की, जो कारखानों को सहाय करने के वैधानिक आवरण के रूप में काम कर रहा है और एक तरह से खड़े-खड़े मिलों को खत्म करने के फैसले सुना रहा है, बर्षों युनियनों द्वारा पेश की गयी संयोजित मिलों के पुनर्जीवन को योजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार, निर्गम नीति को चोर दरवाजे से लागू करने के हथियार के तौर पर, मजदूरों पर कथित स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति श्रेणी जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आये सी आइ टी यू बर्किंग कमेटी सदस्यों का कहना था कि सुनियोजित ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र का खाली करने का अभियान चलाया जा रहा है जिसके चलते, औद्योगिक क्षेत्र में जंगल राज ही कायम हो गया है। विदेशी निवेश तो बढ़ रहे हैं लेकिन, एक ओर घरेलू प्रौद्योगिकी को कमजोर किया जा रहा है और दूसरी ओर, कोई नई प्रौद्योगिकी नहीं आ रही है। इसके

चलते, औद्योगिकरण तथा नये रोजगार पैदा करने की प्रक्रिया के विपरीत, उद्योगों के खाले और गुंजायूर छिने की हो प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

उद्योगिकरण को मौजूदा नीतियों के प्रत्यक्ष नतीजों के रूप में महंगाई, मुद्रास्फीति, चीनो घुमटाल तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित ढंग से तोड़ने आदि की ओर भी ध्यान खींचा गया।

लगभग सभी वक्ताओं ने असंगठित क्षेत्र की स्थिति का जिक्र किया। यह रेखांकित किया गया कि नयी आर्थिक नीतियों के चलते संगठित उद्योगों के भी-भीरे विनियमों की प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में और खासतौर पर गृह-आधारित उद्योगों पर धकेल रहे हैं। इस तरह से, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का और भारी सोपान करने के जरिए, जिनमें बहुसंख्य महिलाओं की है, भारी मुनाफे बटोर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों में असंगठित क्षेत्र में चलाये जा रहे संघर्षों के बारे में भी बताया।

बर्किंग कमेटी सदस्यों ने, अपने-अपने राज्यों में 14 जुलाई को सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल की स्थिति और अन्य प्रमुख संघर्षों के बारे में भी बताया। संगठन के प्रश्नों पर हुई बहस के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने संगठन संस्था रिपोर्ट के पालन पर, आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट पेश की।

कार्यक्रमों के पालन पर हुई बहस में, विभिन्न वक्ताओं ने अपने-अपने राज्यों तथा औद्योगिक फेडरेशनों द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में बताया और भरोसा दिया कि 3 से 9 अगस्त तक के प्रचार सप्ताह से लेकर, 29 सितम्बर को हड़ताल तक, सभी चरणों में लोगों की भारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जायेगी। बहस के बाद, महासचिव की रिपोर्ट और कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट को, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बैठक ने अलग से एक प्रस्ताव पारित कर, नैचुरली लिनाइट कार्पोरेशन के संघर्षशील मजदूरों तथा अफसरों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जघन्य हमले की भर्त्सना की। महासचिव द्वारा रिपोर्ट पर बहस के अपने उतर में और सी आइ टी यू अध्यक्ष ई बालानंदन द्वारा अपने समान भाषण में, 29 सितम्बर की आम हड़ताल को अभूतपूर्व ढंग से कामयाब बनाने का आह्वान किये जाने के साथ, बैठक समाप्त हुई।